



कृषि निर्यात लाभ



भारतीय निर्यात-आयात बैंक
Visit us at www.eximbankagro.in

मई 2018
खंड XXII अंक III

अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड, मलयालम, उडिया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में प्रकाशित

अनुक्रमणिका

| | |
|--|-------|
| परिदृश्य : | |
| चाय उद्योग | 1-2 |
| भारत में कृषि मशीनीकरण: एक अवलोकन | 3-5 |
| भारत में कृषि रसायन उद्योग | 5-7 |
| हल्दी: भारत से संभावित निर्यात | 7-9 |
| तैल फसलों में नीति बदलाव | 9-11 |
| मुख्य समाचार | 11-12 |

परिदृश्य : चाय उद्योग

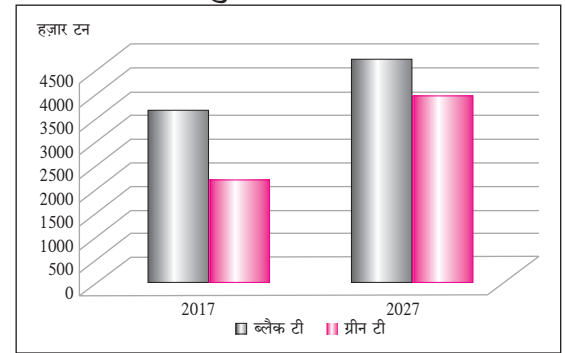
अनुमानित उत्पादन

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, ब्लैक टी का वैश्विक उत्पादन 2.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ते हुए वर्ष 2027 तक 4.42 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। उत्पादन में यह बढ़ोत्तरी की वजह चीन, केन्या और श्रीलंका के चाय उत्पादन में बड़ी वृद्धि हो सकती है। माना जा रहा है कि चीन के चाय उत्पादन में वृद्धि का एक कारण ब्लैक टी की किस्मों, विशेष रूप से प्यु'अर टी की बढ़ती मांग में हो रही वृद्धि भी हो सकता है। भारत का चाय उत्पादन वर्ष 2017 के 1.26 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2027 तक 1.62 मिलियन टन होने का अनुमान है। इसी के साथ उम्मीद जताई जा रही है कि भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक बना रहेगा।

चीन के ग्रीन टी उत्पादन में विस्तार को दर्शाते हुए वर्ष 2027 तक ग्रीन टी का वैश्विक उत्पादन प्रतिवर्ष 7.5 प्रतिशत की उच्च दर से बढ़ते हुए वर्ष 2027 तक 3.65 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। चीन का ग्रीन टी उत्पादन वर्तमान के 1.53 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2027 तक 3.31 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। माना जा रहा है कि चीन के ग्रीन टी उत्पादन में यह वृद्धि उत्पादन क्षेत्र में विस्तार के कारण न होकर उच्च पैदावार वाली किस्मों और बेहतर कृषि प्रणालियों के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि के चलते होगी। वियतनाम में भी 6.8

प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ ग्रीन टी के उत्पादन में काफी वृद्धि होने का अनुमान है।

ब्लैक टी एवं ग्रीन टी का वर्तमान एवं अनुमानित उत्पादन



स्रोत: एफएओ

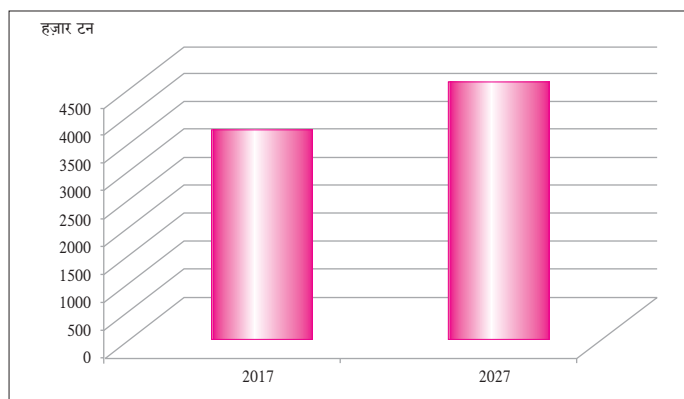
अनुमानित खपत

ब्लैक टी की वैश्विक खपत 2.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2027 तक 4.17 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। यह आँकड़ा दर्शाता है कि परंपरागत चाय आयातक देशों में चाय की खपत में जितनी गिरावट होने वाली है, उससे ज्यादा खपत चाय उत्पादक देशों में बढ़ने वाली है। चाय निर्यात करने वाले देशों में चाय की खपत में होने वाली वृद्धि, चाय आयात करने वाले देशों में चाय की खपत में आने वाली अपेक्षित गिरावट से अधिक है। शीर्ष पांच चाय उत्पादन देशों में सबसे अधिक उत्पादन चीन में होने की उम्मीद है, जहां अगले 10 वर्षों तक प्रतिवर्ष 5.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का अनुमान है। अफ्रीकी देशों में खपत में अधिक वृद्धि का

अनुमान है, जिनमें रवांडा में सबसे अधिक वृद्धि दर (9.0 प्रतिशत) दर्ज किए जाने का अनुमान है। इसके बाद यूगांडा (5.0 प्रतिशत), केन्या (4.4 प्रतिशत), लीबिया (4.4 प्रतिशत), मोरक्को (4.2 प्रतिशत) तथा मलावी (4.2 प्रतिशत) का स्थान है। अन्य चाय उत्पादक देशों में 2.0 से 3.5 प्रतिशत के बीच मध्यम वृद्धि दर रहने का अनुमान है। जैसे- बांग्लादेश में (3.1 प्रतिशत), भारत में (2.2 प्रतिशत), श्रीलंका में (3.3 प्रतिशत), तंजानिया में (1.8 प्रतिशत) और वियतनाम में (2.0 प्रतिशत) वृद्धि दर का अनुमान है। कॉफी सहित अन्य पेय पदार्थों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण पश्चिमी देशों में चाय की खपत में कमी होने का अनुमान है, ब्रिटेन में तो यह लगभग न के बराबर है। तथापि, जर्मनी (1.4 प्रतिशत), पोलैंड (1.3 प्रतिशत), नीदरलैंड और फ्रांस (दोनों 0.6 प्रतिशत) में खपत में वृद्धि इस पूरे क्षेत्र में 0.2 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से अधिक रहने का अनुमान है।

चाय उत्पादक देशों में खपत के विस्तार में योगदान देने वाले प्रमुख कारक हैं - प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, चाय सेवन से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के विषय में बढ़ती जागरूकता तथा चाय की किस्मों में आई विविधता, जो युवाओं सहित ऐसे जनसमूह को आकर्षित कर रही है, जो चाय का परंपरागत उपभोक्ता नहीं है। चीन में ब्लैक टी के सेवन में तीव्र वृद्धि प्यु'अर जैसी ब्रिक चाय की लोकप्रियता के कारण आई है, जिनका प्रचार मूलतः स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाता है।

ब्लैक टी और ग्रीन टी की वर्तमान और अनुमानित खपत

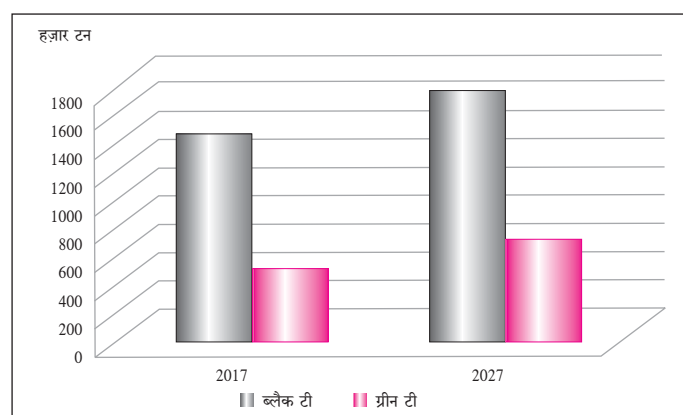


स्रोत: एफ़एओ

अनुमानित निर्यात

अनुमान है कि वर्ष 2017 से 2027 तक अर्थात् 10 वर्ष की अवधि में ब्लैक टी के वैश्विक निर्यात में 2.1 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज की जाएगी, क्योंकि निर्यात मात्रा 1.3 मिलियन टन से बढ़कर 1.7 मिलियन टन होने का अनुमान है। वर्ष 2017 में केन्या से चाय निर्यात की मात्रा 0.4 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया था और अब वर्ष 2027 तक इसके 0.5 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। भारत द्वारा ब्लैक टी का निर्यात 0.4 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है जो वर्ष 2027 तक वैश्विक निर्यात का 21.9 प्रतिशत होगा।

ब्लैक टी एवं ग्रीन टी का वर्तमान एवं अनुमानित निर्यात



स्रोत: एफ़एओ

वर्ष 2027 तक ग्रीन टी का वैश्विक निर्यात सालाना 5.0 प्रतिशत की दर से बढ़ते हुए 0.6 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। 0.4 मिलियन टन की निर्यात मात्रा के साथ चीन के निर्यात बाजार में आगे बने रहने की संभावना है। इसके बाद वियतनाम, इंडोनेशिया और जापान का स्थान आता है। ग्रीन टी निर्यात वृद्धि दर के मामले में जापान और वियतनाम के क्रमशः 9.3 प्रतिशत और 9.0 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ अग्रणी रहने की उम्मीद है, जो चीन की वृद्धि दर (4.0 प्रतिशत) की तुलना में दोगुनी से भी अधिक होगी।

संदर्भ:

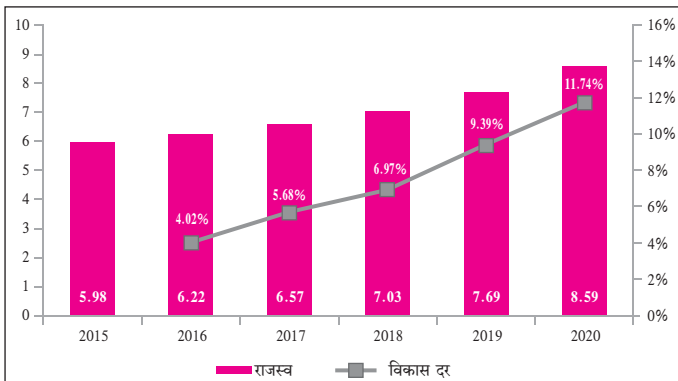
➤ खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ़एओ)

भारत में कृषि मशीनीकरण: एक अवलोकन

भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप किसान की आय में भी वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक कारण कृषि मशीनीकरण को बड़े पैमाने पर अपनाया जाना है, जो कि हरित क्रांति के बाद से पहली बार सामने आया है। मशीनीकरण के विकास ने ट्रैक्टर, थ्रेसर्स, कटाई मशीन, कम्बाइन मशीन, इलैक्ट्रिक मोटर, डीजल इंजन और पंपिंग सेट जैसी विभिन्न प्रकार की मशीनों की मांग को बढ़ाया है। कृषि उपकरण विक्रेताओं के मार्केटिंग नेटवर्क में भी समय के साथ सुधार हुआ है, जिसके कारण किसानों के लिए कृषि मशीनों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है।

ट्रैक्टर, पौध संरक्षण उपकरण, कटाई करने वाले यंत्र, ड्रिप सिंचाई उपकरण तथा माइक्रोस्प्रींकलर इत्यादि कृषि मशीनरी निर्माण के क्षेत्र में भारत को अग्रणी देश माना जाता है। बढ़ती जनसंख्या की निरंतर खाद्य आपूर्ति के लिए कृषि क्षेत्र पर बढ़ते दबाव के कारण देश में कृषि मशीनीकरण की मांग में वृद्धि हुई है। भारत में कृषि मशीनीकरण बाजार 2015 में 5.98 अरब यूएस डॉलर का था, जिसके 2020 तक 7.5% की सीएजीआर से बढ़ते हुए 8.59 अरब यूएस डॉलर का होने की उम्मीद है।

कृषि मशीनीकरण बाजार (अरब यूएस डॉलर)



स्रोत : टेक्नेवियो एनालिसिस

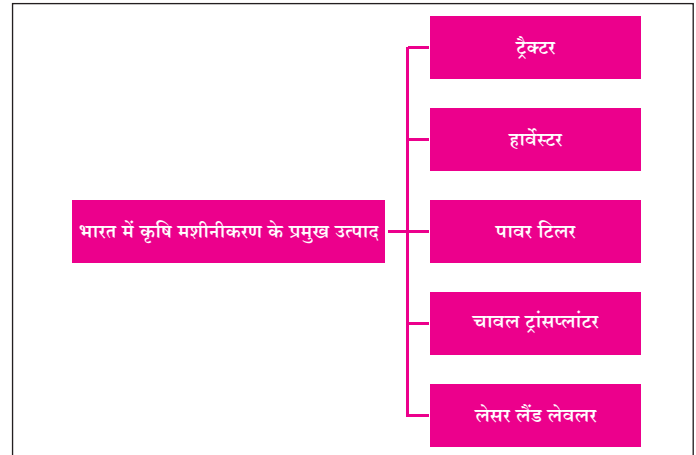
कृषि मशीनरी कृषि मूल्य शृंखला में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन प्रक्रियाओं में मशीनरी का उपयोग नीचे दिखाया गया है:

कृषि मूल्य शृंखला में कृषि मशीनरी की भूमिका



स्रोत : टेक्नेवियो एनालिसिस

कृषि मशीनीकरण: विभिन्न प्रकार



स्रोत : टेक्नेवियो एनालिसिस

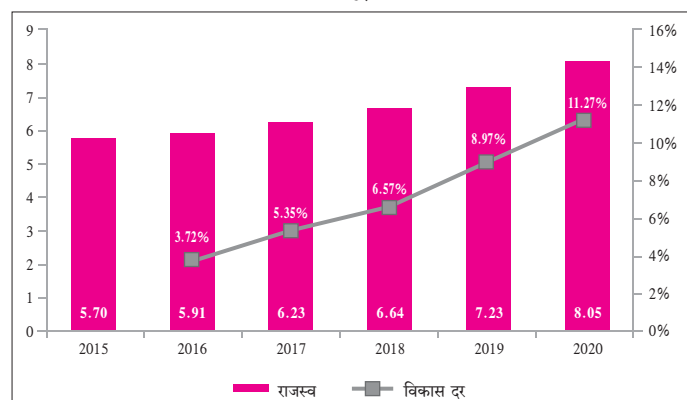
भारत में ट्रैक्टर बाजार:

भारत दुनिया के सबसे बड़े ट्रैक्टर विनिर्माताओं में से एक है। कृषि मशीनीकरण बढ़ने से ट्रैक्टरों की बिक्री में भी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों के कम उपलब्ध होने के कारण भी देश में भारत में ट्रैक्टरों की बिक्री बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए भोजन, उर्वरक, कृषि उपकरण तथा कृषि ऋण में छूट देने वाले

कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी के कारण भारत में ट्रैक्टर बाजार को मजबूती से बढ़ने में मदद मिली है। महिंद्रा और टैफे जैसी भारतीय कंपनियां भारत में ट्रैक्टर बाजार का एक बड़ा हिस्सा रखती हैं।

उच्च जनसंख्या वृद्धि द्वारा भोजन की बढ़ती मांग के कारण कृषि ट्रैक्टरों की मांग में भी वृद्धि होती रहेगी। इसके अलावा, बीजों और उर्वरकों जैसी सामग्री की बढ़ती कीमतों को तकनीकी रूप से उन्नत ट्रैक्टरों का इस्तेमाल कर संतुलित किया जा सकता है, जो उपज बढ़ाने में भी मददगार होते हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया से ट्रैक्टरों की उच्च मांग भी ट्रैक्टर निर्माण क्षेत्र को स्थिर दर से बढ़ने में मदद कर रही है। चूँकि उच्च-हॉर्स पावर मशीन बहु-कार्यात्मक हैं, अतः वे कृषि उत्पादन में वृद्धि में सहायक हो सकती हैं। बाजार में प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए निर्माता ट्रैक्टरों की कीमत कम कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-2020 तक भारत में ट्रैक्टर बाजार (बिलियन यूएस डॉलर)



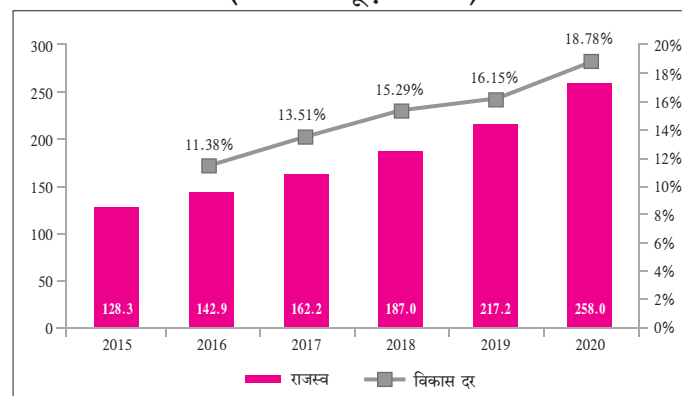
स्रोत : टेक्नेवियो एनालिसिस

भारत में कटाई मशीन (हार्वेस्टर) बाजार:

कटाई मशीन (कम्बाइन हार्वेस्टर) का उपयोग फसलों की कटाई के लिए किया जाता है। ये कटाई के तीन कार्य - काटने, विनोपन (ओसाई, फटकना) और थ्रेसिंग के काम आते हैं। अतः इन्हें कम्बाइन हार्वेस्टर कहा जाता है। एक ही मशीन से तीन प्रमुख काम हो जाने से श्रमिकों की कमी वाले देशों में इस उपकरण की लोकप्रियता बढ़ गई है। जई, राई, जौ, ज्वार, सोयाबीन, मक्का,

सन (फ्लेक्स), सूरजमुखी, कैनोला और गेहूँ जैसी फसलों की कटाई हार्वेस्टर से की जा सकती है। अनुमान है कि भारत में हार्वेस्टर बाजार, वर्ष 2015 से वर्ष 2020 के बीच 15.0% की सीएजीआर से बढ़ते हुए 258 मिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2015-2020 तक भारत में हार्वेस्टर बाजार (मिलियन यूएस डॉलर)

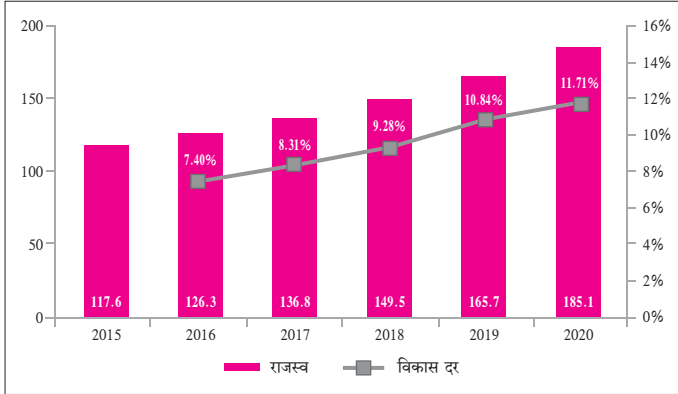


स्रोत : टेक्नेवियो एनालिसिस

भारत में पावर टिलर बाजार

कृषि मशीनीकरण पर सरकार के बढ़ते फोकस ने भारत में पावर टिलर बाजार को बढ़ाने का काम किया है। भारत में पावर टिलरों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि उन्हें आसानी से छोटे क्षेत्रों में भी प्रयोग किया जा सकता है और भूमि समतल करने में लगने वाले समय को काफी कम किया जा सकता है। ट्रैक्टर की तुलना में उन्हें, जमीन की प्रति इकाई के अनुसार अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है और ये धान की खेती में बहुत उपयोगी होते हैं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों में जहां सिंचाई उपलब्ध है, वहाँ किसान धान की मुख्य फसल के बाद दूसरी फसल बो देते हैं। इसके लिए एक अलग प्रकार की जुताई की आवश्यकता होती है, और पावर टिलर्स इस आवश्यकता को पूरा करते हैं। अतः देश में धान की फसलें पावर टिलर विक्रेताओं को एक शानदार अवसर प्रदान करती हैं। डीजल की लागत कम होती है, अतः पेट्रोल टिलरों की अपेक्षा डीजल - टिलरों को प्राथमिकता दी जाती है। भारत में पावर टिलर बाजार के वर्ष 2015 के 117.6 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2020 में 185.1 मिलियन यूएस डॉलर हो जाने का अनुमान है।

भारत में पावर टिलर बाजार राजस्व (मिलियन यूएस डॉलर)



स्रोत : टेक्नेवियो एनालिसिस

चुनौतियाँ

कृषि उपकरण, विशेष रूप से कम ऊर्जा खपत वाले उपकरण भारत के किसानों के लिए महंगे और एक तरह से बड़ा पूँजीगत निवेश हैं। भारत में अधिकांश किसान अल्प आय वर्ग के हैं, जिनमें से 80% से अधिक सीमांत और छोटे किसान हैं। ये किसान भारी और तकनीकी रूप से उन्नत मशीनों को खरीदने में वित्तीय रूप से सक्षम नहीं हैं। भारत में बेचे जाने वाले लगभग 90% ट्रैक्टर विभिन्न वित्तीय संस्थानों की सहायता से खरीदे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि कार्य बड़े पैमाने पर भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है, अतः वहाँ सेवा केन्द्रों की कमी के कारण कृषि उपकरणों की भली प्रकार से देख-रेख करना भी एक चुनौती है। उचित

देखभाल की कमी मशीन की जीवन अवधि और दक्षता को प्रभावित करती है। अतः कृषि उपकरणों के ऊँचे दाम और इनकी बिक्री के बाद की उचित देखभाल की कमी के कारण किसान मशीनों की खरीद और उनका प्रयोग करने में हिचकते हैं तथा श्रमिकों और बैल-गाड़ियों का उपयोग करके खेती के पुराने व अक्षम तरीकों पर आश्रित रहते हैं।

ट्रैक्टरों तथा अन्य कृषि मशीनों में अधिकतर डीजल इंजन होते हैं, जो पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करते हैं। ये इंजन नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का संयुक्त उत्सर्जन करते हैं। यद्यपि पौधों को अपने विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन उनमें खनिज पोषक तत्वों को असंतुलित कर सकती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता के कारण स्वास्थ्य समस्याएँ, जैसे- साँस लेने में कठिनाई या अम्लीय वर्षा हो सकती है। यह आवश्यक हो गया है कि निर्माता कम उत्सर्जन वाले इंजन विकसित करने के लिए अपने अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान दें। चूँकि ट्रैक्टर औसतन 25 वर्ष चलता है, इसलिए देश में अभी भी ट्रैक्टरों के पुराने मॉडल खूब प्रयोग हो रहे हैं, इन्हें बदलने में अभी काफी समय लगेगा।

संदर्भ:

➤ टेक्नेवियो एनालिसिस

भारत में कृषि रसायन उद्योग

कृषि रसायन फसल उत्पादन में एक मूलभूत सामग्री बन गए हैं, जो कृषि क्षेत्र में बदलती वैश्विक माँगों को पूरा करने, उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाने और फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम हैं। इन रसायनों के विभिन्न खंडों में कीटनाशक, कवक (फफूंदनाशी), तृणनाशक (हर्बिसाइड) और पौधों को बढ़ाने वाले पदार्थ, नेमाटोसाइड, कृतक (रोडेन्टोसाइड), धूमक (फ्यूगिमेंट) आदि शामिल हैं। प्रौद्योगिकी में विकास के परिणामस्वरूप फलोत्पादक कृषि रसायनों का काफी विकास हुआ है। यूएस, जापान और चीन के बाद भारत विश्व स्तर पर कृषि रसायनों का

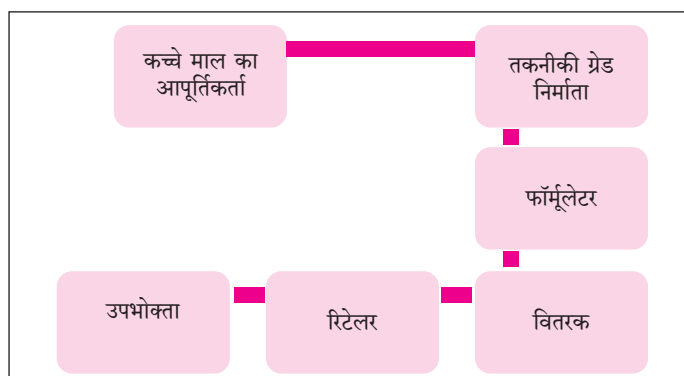
चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है और अपने उत्पादन का लगभग 50% भाग निर्यात करता है।

भारतीय परिदृश्य

देश का कृषि रसायन उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। कपास के बाद कीटनाशकों की सबसे अधिक आवश्यकता धान के लिए पड़ती है, जिसका उत्पादन एवं उपभोग भूमि तथा जलवायु की उपयुक्तता के कारण देश में बड़े पैमाने पर होता है।

भारत का नाम दुनिया में सबसे कम कृषि रसायन उपभोग वाले देशों

कृषि रसायन उद्योग की संरचना



में आता है। देश की बढ़ती आबादी और इसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति भूमि अधिग्रहण में आई गिरावट को देखते हुए उत्पादकता में सुधार करने के नजरिए से कृषि रसायन का महत्त्व और भी बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में कृषि रसायन की सहज उपलब्धता से घरेलू खपत तेजी से बढ़ी है और विक्रेताओं ने अपने कार्य को विस्तार देते हुए विक्रय के साथ-साथ उत्पादन रणनीतियां भी अपना ली हैं। इस तरह निर्यात स्तर के बढ़ने की भी संभावनाएँ हैं।

भारत में, लगभग 125 तकनीकी ग्रेड निर्माता, 500 फॉर्मूलेटर्स और 145,000 से अधिक वितरक हैं। साठ तकनीकी ग्रेड कीटनाशकों का निर्माण देशी प्रक्रिया से किया जा रहा है। तकनीकी ग्रेड निर्माता शुद्ध तेज़ रसायनों को आमतौर पर 200-250 किग्रा के ड्रमों में भरकर थोक में फॉर्मूलेटर्स को बेचते हैं। इसके बाद, फॉर्मूलेटर्स इसमें ऐसे पदार्थ मिलाकर एक मिश्रण तैयार करते हैं, जो अन्य

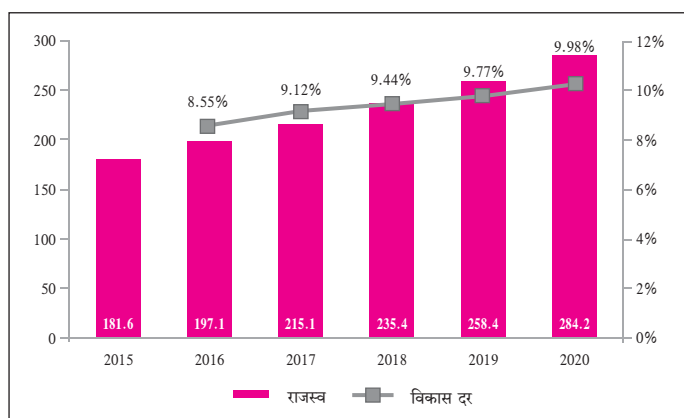
रसायनों से मिलकर निष्क्रिय रहते हैं और घुलनशील होते हैं। इसमें गंधनाशक और सरफेस एक्टिव एजेंट भी मिले होते हैं। फिर इन निर्मित वस्तुओं को खुदरा बिक्री के लिए पैक किया जाता है और इसके बाद इन्हें वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से किसानों को बेचा जाता है।

उत्पादन

वर्ष 2011-2015 के दौरान भारत में कृषि रसायन बाजार में पर्याप्त प्रगति हुई है। इसका उत्पादन वर्ष 2011 में 146 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2015 में 181.6 हजार मीट्रिक टन तक पहुंच गया और इस दौरान 5.6 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज की गई। अब वर्ष 2020 तक भारत में कृषि रसायन बाजार के 9.4 प्रतिशत के सीएजीआर के साथ 284.2 हजार मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है।

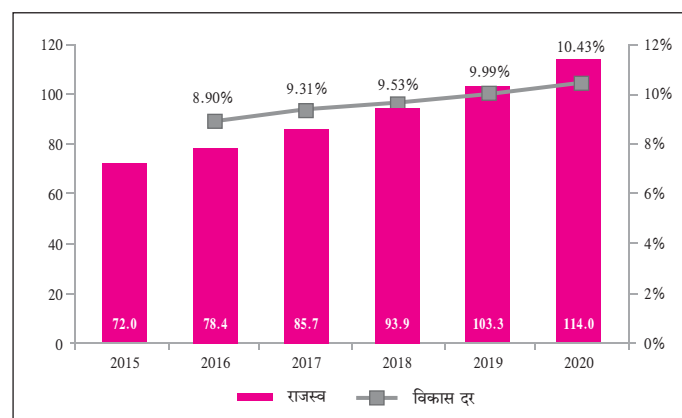
बढ़ती जनसंख्या के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि की मांग भी बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य उत्पादन की मांग में वृद्धि के साथ कृषि भूमि और कृषि श्रमिकों में कमी आई है। इसने, अत्यधिक मजदूरी देकर श्रमिकों द्वारा खेतों में निराई करवाने के बजाय किसानों को तृणनाशक (हर्बिसाइड) दवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा, किसानों के बीच बढ़ती जागरूकता और नकदी फसलों (जिसमें कृषि रसायनों की जरूरत अधिक होती है) की ओर बढ़ते उनके झुकाव ने देश में कृषि रसायनों की मांग में वृद्धि की है।

भारत में कृषि रसायन का उत्पादन (हजार मीट्रिक टन)



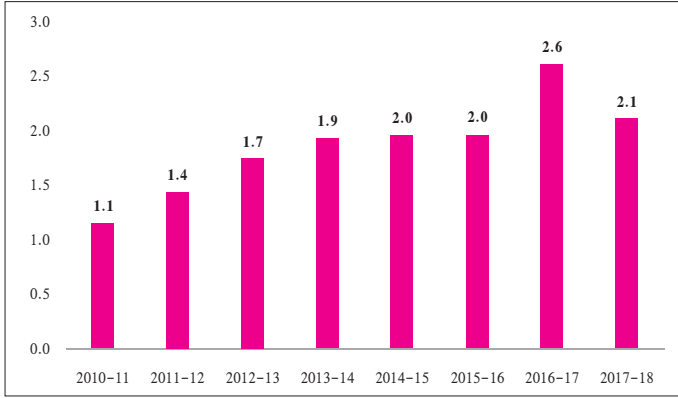
स्रोत : टेक्नेवियो एनालिसिस

भारत में कृषि रसायन की खपत (हजार मीट्रिक टन)



स्रोत : टेक्नेवियो एनालिसिस

भारत द्वारा कृषि रसायनों का निर्यात (अरब यूएस डॉलर)



स्रोत: डीजीसीआईएस

खपत

वर्ष 2011 के दौरान भारत में कृषि रसायनों की खपत लगभग 70.3 हजार मीट्रिक टन थी तथा इस अवधि के दौरान 0.6 प्रतिशत का मामूली सीएजीआर दर्ज करते हुए वर्ष 2015 में मामूली वृद्धि के साथ यह 72 हजार मीट्रिक टन तक पहुंच गई। वर्ष 2015 से वर्ष 2020 के दौरान 9.6 प्रतिशत का सीएजीआर दर्ज करते हुए भारत में वर्ष 2020 तक कुल कृषि रसायन खपत 114 हजार मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है।

निर्यात

भारत से कृषि रसायनों का निर्यात निरंतर बढ़ रहा है तथा वर्ष 2016-17 में यह 2.6 अरब यूएस डॉलर तक जा पहुँचा। फिर वर्ष 2017-18 में वापस 2.1 अरब यूएस डॉलर तक गिरने से पहले वर्ष दर वर्ष आधार पर इसमें 32.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कृषि रसायनों के निर्यात में 2010-11 से 2017-18 के दौरान 9.1% की अच्छी सीएजीआर दर्ज की गई।

संभावना

भारत में अनाज की बढ़ती मांग और भूमि की कमी के कारण कृषि क्षेत्र में सुधार लाने तथा फसल को कीटों से बचाने के लिए दबाव लगातार बढ़ रहा है। अनुमान है कि यह रुख भविष्य में भी जारी रहेगा, जो भारत में कृषि रसायन बाजार के विकास को उत्प्रेरित करेगा।

संदर्भ:

- टेक्नेवियो एनालिसिस
- वाणिज्य मंत्रालय

हल्दी: भारत से संभावित निर्यात

भारत विश्व में हल्दी का अग्रणी उत्पादक है और वैश्विक हल्दी उत्पादन का लगभग 80% हिस्से का उत्पादन करता है। भारत के अलावा चीन, म्यांमार, नाइजीरिया और बांग्लादेश इत्यादि अन्य देश भी हल्दी का उत्पादन करते हैं।

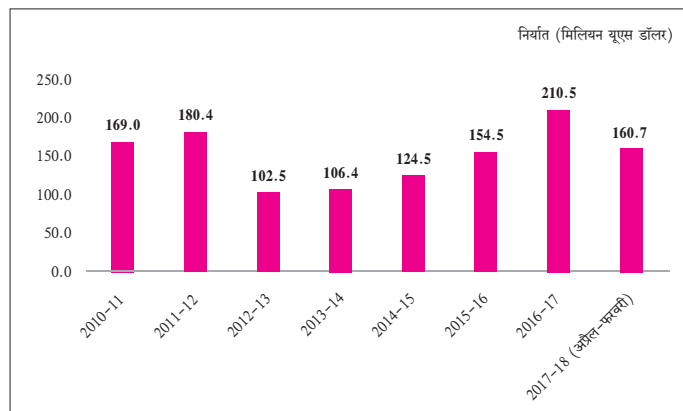
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-16 के दौरान हल्दी की खेती का क्षेत्र लगभग 185 हजार हेक्टेयर था, जिसका उत्पादन 95% हजार मीट्रिक टन था। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल भारत के प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य हैं।

निर्यात

भारत द्वारा वर्ष 2010-11 से 2016-17 के दौरान हल्दी (एचएस कोड 091030) के निर्यात में 3.7% की सीएजीआर दर्ज की गई। वर्ष 2012-13 के दौरान, हल्दी के निर्यात में तेजी से गिरावट आई थी और निर्यातों का मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 43% तक गिर गया था। हालाँकि वर्ष 2014-15 में हल्दी का निर्यात 17% की वृद्धि दर्ज करते हुए ऊँचाई पर पहुँच गया। इसके बाद के वर्षों में हल्दी के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। प्रतिवर्ष 36.2% की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2016-17 में हल्दी के निर्यात का मूल्य 210.5 मिलियन यूएस डॉलर हो गया। वर्ष 2017-18

(अप्रैल-फरवरी) में 160.7 मिलियन यूएस डॉलर के निर्यात का अनुमान है।

भारत द्वारा हल्दी का निर्यात



स्रोत: डीजीसीआईएस

निर्यात क्षेत्र में हल्दी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हल्दी में बहुत उछाल दिख रहा है। यह देखा जाता है कि वैश्विक स्तर पर अन्य मसालों की तुलना में हल्दी का व्यापार तीव्र एवं स्थिर है। हल्दी की खेती के लिए भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कोझिकोड, केरल और राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसंधान को सहयोग प्रदान किया जाता है। एपीडा ने राज्य से हल्दी के निर्यात को बढ़ाने के लिए ओडिशा में हल्दी उगाने हेतु कृषि निर्यात क्षेत्र अधिसूचित किया है।

भारत से हल्दी का सबसे प्रमुख निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका है तथा वर्ष 2016-17 की अवधि में कुल निर्यात का 12% भाग अमेरिका को ही निर्यात किया गया। वर्ष 2017-18 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान निर्यात 28.8 मिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें अमेरिका का हिस्सा बढ़कर 17.9% हो गया। वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के हल्दी निर्यात में 9.2% की हिस्सेदारी के साथ ईरान भारत से हल्दी का दूसरा सबसे बड़ा आयातक था। संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, ब्रिटेन, मोरक्को, श्रीलंका, जर्मनी, जापान और नीदरलैंड भारतीय हल्दी के अन्य प्रमुख निर्यात स्थल हैं।

भारतीय हल्दी के प्रमुख आयातक

| देश | 2016-17 | 2017-18 (अप्रैल-फरवरी) |
|----------|------------------|------------------------|
| | मिलियन यूएस डॉलर | |
| यूएसए | 25.2 | 28.8 |
| ईरान | 20.2 | 14.8 |
| यूएई | 11.4 | 9.4 |
| मलेशिया | 9.6 | 9.2 |
| यूके | 8.2 | 6.9 |
| मोरक्को | 6.7 | 6.7 |
| श्रीलंका | 6.7 | 6.0 |
| जर्मनी | 7.1 | 5.8 |
| जापान | 6.0 | 4.9 |
| नीदरलैंड | 5.2 | 4.7 |
| कुल | 210.44 | 160.66 |

स्रोत: डीजीसीआईएस

प्रमुख वैश्विक बाजार

वैश्विक स्तर पर यूएसए हल्दी का सबसे प्रमुख आयातक रहा है, इसकी आयात मांग के अधिकतर भाग को भारत द्वारा पूरा किया जा रहा है। यूएसए को हल्दी की आपूर्ति करने वाले अन्य महत्वपूर्ण देश चीन, फिजी और जमैका हैं। पिछले दिनों, प्रसंस्कृत खाद्य उद्योगों में हल्दी के पाक गुणों की जानकारी के अलावा हल्दी के पौष्टिक और औषधीय मूल्यों के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण यूएसए में हल्दी की बढ़ती मांग को नोट किया गया है। अमेरिका में पेय के रूप में हल्दी के अर्क सहित खानपान में हल्दी का उपभोग और बढ़ने की संभावना है। पिछले पांच वर्षों के दौरान यूएसए द्वारा भारत से हल्दी का आयात मूल्य वर्ष 2013 में 14.2 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर वर्ष 2017 में 35.1 मिलियन यूएस डॉलर हो गया।

मध्य पूर्व, विशेष रूप से ईरान, यूएई और सऊदी अरब में भारतीय हल्दी की मांग बहुत अधिक है। वैश्विक स्तर पर ईरान हल्दी का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है और इसके प्रमुख आपूर्तिकर्ता

भारत, यूएई और पाकिस्तान हैं। पिछले कुछ वर्षों से ईरान द्वारा हल्दी का आयात लगातार बढ़ रहा है।

वर्ष 2016-17 में ब्रिटेन को 8.2 मिलियन यूएस डॉलर मूल्य हल्दी निर्यात की गई थी। वर्ष 2017 के दौरान ब्रिटेन द्वारा कुल हल्दी आयात का लगभग 68.5% हिस्सा भारत से आयात किया गया। इसके बाद नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत से आयात क्रमशः 7.5%, 6.4% 4.9% और 3.8% रहा।

जर्मनी विश्व में हल्दी का पांचवां सबसे बड़ा आयातक है, और वर्ष 2017 में इसके आयात का मूल्य 11.4 मिलियन यूएस डॉलर रहा। जर्मनी में आयातित हल्दी के लिए 58.8% के हिस्से के साथ इस उत्पाद का सबसे प्रमुख आपूर्तिकर्ता भारत रहा। वर्ष 2017 में

जर्मनी को हल्दी के अन्य प्रमुख आपूर्तिकर्ता क्रमशः 7.9%, 7.1%, 6.3% और 3.8% प्रतिशत हिस्से के साथ नीदरलैंड, मेडागास्कर, पेरू तथा थाईलैंड थे।

मलेशिया विश्व स्तर पर हल्दी का छठा सबसे बड़ा आयातक है। वर्ष 2017 के दौरान मलेशिया में आयातित कुल हल्दी का 91.7% हिस्सा भारत से निर्यात किया गया। बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और इंडोनेशिया क्रमशः 3.8%, 1.8%, 1.2% और 0.6% हिस्से के साथ अन्य प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहे।

संदर्भ:

- एपीडा
- कृषि मंत्रालय

तैल फसलों में नीति बदलाव

| देश | उत्पाद | तिथि | नीतिगत श्रेणी / उपाय | विवरण |
|--------------------|-----------------|-------------|-------------------------|--|
| ऑस्ट्रेलिया / पेरू | सफेद सरसों | नवंबर 2017 | द्विपक्षीय व्यापार करार | ऑस्ट्रेलियाई सफेद सरसों को पेरू में कर-मुक्त प्रवेश देने पर सहमति बनी। |
| चीन | सोयाबीन / मक्का | नवंबर 2017 | कृषि नीति | देश की अनाज भंडारण व्यवस्था को अधिक लचीला बनाते हुए हेलोंगजियांग प्रांत में मक्का पर नियंत्रण एवं सोयाबीन को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ किसानों को भुगतान में सामंजस्य बैठाया। अनाज परिवहन तथा भंडारण सुविधा को सहायता प्रदान करने की घोषणा भी की। |
| | सोयाबीन | नवंबर 2017 | सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग | सोयाबीन की सार्वजनिक नीलामी को 1 नवंबर 2017 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, ताकि 2017/18 की नई फसल की मार्केटिंग में नुकसान न हो। |
| | गेहूँ, सोयाबीन | दिसंबर 2017 | खाद्य मानक | सोयाबीन समेत अन्य अनाज प्रसंस्करण हेतु स्वच्छता पद्धति (हाईजीन) अपनाने के लिए एक नए कोड का विमोचन किया। |
| | सोयाबीन | दिसंबर 2017 | व्यापार मानक | पिछली खेप में खरपतवार जैसी अशुद्धियों को देखते हुए यूएस के लिए सोयाबीन कार्गो में अशुद्धियों का स्तर घटाया गया। |

| | | | | |
|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|---|
| चीन | सफेद सरसों का तेल | जनवरी 2018 | सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग | सरकारी भंडार में कमी के चलते राज्य भंडार द्वारा सफेद सरसों के तेल की सार्वजनिक नीलामी को स्थगित कर दिया गया। |
| | सोया वाला खाना | मार्च 2018 | क्षेत्र विकास उपाय | सोयाबीन को खाने तथा खाद्य उत्पाद में प्रसंस्कृत करने वाले उद्योगों को सीधा समर्थन भुगतान देने से संबंधित जानकारी देना। |
| यूरोपीय संघ | ग्लाइफोसेट | नवंबर 2017 | कीटनाशक विनियमन | 5 वर्ष के सीमित समय के लिए विवादास्पद हर्बीसाइडों के प्रयोग की अनुमति दी गई, ताकि अन्न तथा तिलहन के व्यापार में हानि न हो। |
| | बायोडीजल | दिसंबर 2017 | जैव ईंधन नीति | इसकी पुष्टि की गई कि ऑस्ट्रेलिया व कनाडा में उगने वाली सफेद सरसों पर्यावरण के अनुकूल है तथा जैवडीजल के भंडारण के लिए उपयुक्त है, अतः इसे ईयू मार्केट में प्रयोग किया जा सकता है। |
| | तिलहन | दिसंबर 2017 | जीएमओ नीति | भोजन एवं भोज्य पदार्थों के उपयोग के लिए सोयाबीन की तीन तथा सफेद सरसों की दो किस्मों समेत जीएम फसल की एक नई किस्म को प्राधिकृत किया गया। |
| | बायोडीजल | जनवरी 2018 | व्यापार विवाद | विश्व व्यापार संगठन के (डब्ल्यूटीओ) विवाद निपटान निकाय द्वारा अधिसूचित किया गया कि इंडोनेशिया से आयातित जैव डीजल से संबंधित इस ब्लॉक की एंटी-डम्पिंग ड्यूटी डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुरूप नहीं थी। |
| | बायोडीजल | मार्च 2018 | जैव ईंधन नीति | यह देखा गया कि यूरोप की संसद इस ब्लॉक के अक्षय ऊर्जा निदेश को वोट करेगी, इससे फसल आधारित जैव ईंधन के उत्पादन को 2017 के स्तर तक लाया जा सकेगा और सड़क / रेल परिवहन ईंधन में उनकी सीमा निर्धारित की जा सकेगी। ii) वर्ष 2021 तक जैव-ईंधन का प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से भूमि परिवर्तन हो रहे हैं। |
| भारत | खाद्य तेल | नवंबर 2017 | आयात नीति | सोयाबीन तेल और खाद्य तेलों पर आयात मूल्य बढ़ा दिया गया है, ताकि इन तेलों के आयात पर नियंत्रण लगाया जा सके और स्थानीय किसानों और प्रसंस्करण करने वालों की आय में वृद्धि की जा सके। |
| | रबी तेल की फसलें | नवंबर 2017 | कृषि नीति | रबी की फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है, तथापि राज्य एजेंसियों द्वारा यह निर्धारित मूल्य पर खरीदा जाएगा। |
| | सोयामील | दिसंबर 2017 | निर्यात संवर्धन | सोयामील शिपमेंट के लिए देश के निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया गया। |
| | खाद्य उत्पाद | फरवरी 2018 | आयात नीति | देश के सामान्य आयात करों में 10 प्रतिशत का अतिरिक्त सीमा-शुल्क लगाकर इसमें संशोधन किया गया है। यह अतिरिक्त कर खाद्य पदार्थों तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों भोजन के आयात पर भी लागू होगा। |

| | | | | |
|------------|---------------------|------------|--------------------|---|
| | चुनिंदा वनस्पति तेल | फरवरी 2018 | आयात नीति | कुछ चुनिंदा (कच्चे व परिष्कृत) वनस्पति तेलों पर आयात कर में वृद्धि की गई। |
| इज़रायल | जैतून का तेल | नवंबर 2017 | आयात नीति | जैतून के तेल के आयात पर कर-मुक्ति में क्रमिक वृद्धि की घोषणा की गई, ताकि उपभोक्ताओं को यह सस्ते दामों में उपलब्ध हो तथा स्थानीय जैतून के तेल की खपत में वृद्धि हो। |
| इंडोनेशिया | पाम ऑयल | नवंबर 2017 | क्षेत्र विकास उपाय | पाम ऑयल के छोटे उत्पादकों के लिए एक योजना तैयार की, जिससे कि छोटे-छोटे प्लांटेशन में उपज बढ़ाई जा सके। नई योजना के पहले चरण में 20000 हैक्टेयर में इंडोनेशियन सस्टेनेबल पाम ऑयल (आईएसपीओ) प्रमाणित पौधारोपण किया जाएगा। |
| मेक्सिको | तिलहन | मई 2018 | कृषि नीति | निम्नलिखित राष्ट्रीय कार्यक्रमों का नवीकरण किया गया: (i) तिलहन के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन (ii) उत्पादक क्रियाओं में निवेश करने के लिए किसानों को नकदी उपलब्ध कराना; तथा (iii) भावी बिक्री को प्रोत्साहित करना। |

स्रोत: एफएओ

मुख्य समाचार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने नाबार्ड फंड खोलने के लिए जारी की फूड पार्कों की समेकित सूची

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को और अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 2000 करोड़ रुपए की निधि प्रदान करने के उद्देश्य से फूड पार्कों की समेकित सूची जारी की है।

इस सूची में मेगा पार्क, फूड पार्क, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक एस्टेट, निजी पार्क, एकीकृत आधारभूत संरचना विकास केंद्र, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, औद्योगिक विकास केंद्र, एकीकृत फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर और औद्योगिक परिसरों समेत कुल 201 पार्क शामिल हैं। यह पहल नाबार्ड में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा खाद्य प्रसंस्करण निधि वर्ष 2015-16 से नामित फूड पार्कों में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी।

2,000 करोड़ रुपए की शुरुआती निधि वाले नाबार्ड फंड की घोषणा केंद्र सरकार ने वर्ष 2014-15 के अपने बजट प्रस्ताव में की थी। लेकिन इस निधि के प्राप्तकर्ता बहुत कम थे, जो इकाइयों को 9.25 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध थी। यह निधि केवल फूड पार्कों के लिए ही थी, अतः इसका एक बड़ा हिस्सा अब तक वितरित नहीं किया जा सका है।

तथापि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की घोषणा के बाद से अधिक क्लस्टर स्थापित होने की उम्मीद है तथा अब इस निधि का उपयोग किया जाएगा। वर्ष 2015-16 में नामित पार्कों की संख्या 150 आंकी गई थी। पिछले तीन वर्षों में, इस सूची में 51 फूड पार्क शामिल किए गए हैं।

संदर्भ:

➤ एफएनबी न्यूज

भारत में नारियल की खेती का विस्तार

भारत में 2010 से 2014 के बीच 9,561 हेक्टेयर के मुकाबले वर्ष 2014 से 2018 के दौरान नारियल बागान योजना के तहत 13,117 हेक्टेयर (हेक्टेयर) क्षेत्र में नारियल के बागान तैयार किए गए। वर्ष 2013-14 में 10,122 के मुकाबले वर्ष 2017-18 में उत्पादकता 11,516 फल प्रति हेक्टेयर हो गई। पिछले चार वर्षों में देश ने नारियल की खेती में अभूतपूर्व प्रगति की है तथा फलों के उत्पादन और उत्पादकता दोनों क्षेत्रों में अग्रणी बन गया है। नारियल के उत्पादन में वृद्धि के कारण, भारत अप्रैल 2017 से मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका को नारियल का तेल निर्यात कर रहा है। इसके अलावा, देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों को बड़ी मात्रा में शुष्क नारियल का निर्यात शुरू कर दिया है। वर्ष 2017-18 के दौरान, भारत ने 1,602.38 करोड़ रुपए के नारियल का निर्यात किया, जबकि आयात 259.70 करोड़ रुपए रहा।

नारियल उत्पादक राज्यों में, वित्तीय वर्ष 2010-14 के दौरान 36,477 हेक्टेयर भूमि पर नारियल की खेती की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014 से 18 तक 62,403 हेक्टेयर भूमि पर वैज्ञानिक तरीके से नारियल की खेती की गई। उल्लेखनीय है कि नारियल की खेती अतिरिक्त क्षेत्रों में भी फैल रही है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2014 से 2018 के दौरान 5,115 नारियल उत्पादन समितियां, 430 नारियल उत्पादक संघ और 67 नारियल उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया था। जबकि वित्तीय वर्ष 2010 से 2014 के दौरान इनकी संबंधित संख्या क्रमशः 4,467, 305 और 15 थी। वित्तीय वर्ष 2004 से 2014 के बीच नारियल उत्पादों के निर्यात से आय की अनुमानित राशि 3,975 करोड़ रुपए थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2014 से 2018 के बीच नारियल के निर्यात से आय 6,448 करोड़ रुपए आंकी गई।

‘फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री’ के अंतर्गत नारियल क्षेत्र के लिए कौशल विकास कार्यक्रम में वर्ष 2004 से 2014 के बीच 27,770 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित किया गया था, जबकि 2014 से 2018 के दौरान 33,228 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।

संदर्भ:

➤ एफएनबी न्यूज़

अप्रैल 2018 में कृषि निर्यात में 11% की वृद्धि

चालू वित्तीय वर्ष में कृषि निर्यात के क्षेत्र में भारत की अच्छी स्थिति रही। अप्रैल 2018 माह के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में शिपमेंट में 11.4 प्रतिशत (₹10,312 करोड़) और डॉलर में 9.5 प्रतिशत यानी 1,571 मिलियन यूएस डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई।

गैर-बासमती चावल की अधिक मांग के चलते भारतीय कृषि की सबसे बड़ी कमोडिटी चावल का निर्यात 12 फीसदी बढ़कर 9.89 लाख टन पहुंच गया। इसी तरह, भैंस के मांस का शिपमेंट 11 प्रतिशत बढ़कर 95,296 टन हो गया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के अस्थायी बयान के अनुसार, दालों और डेयरी उत्पादों के शिपमेंट में भी अप्रैल माह के दौरान वृद्धि दर्ज की गई है।

हालांकि, इस अवधि के दौरान ग्वारगम, गेहूं, ताजा सब्जियों और फलों जैसे उत्पादों के निर्यात में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। ग्वारगम का निर्यात अपने मूल से चौथाई यानी 40,405 टन तक घट गया, जबकि गेहूं का शिपमेंट 70 फीसदी घटकर 11,838 टन रह गया।

संदर्भ:

➤ बिजनेस लाइन्स

यहाँ प्रकाशित समाचार और सूचनाएँ ऐसे विभिन्न स्रोतों से ली गई हैं, जो कि विश्वसनीय माने जाते हैं। हालाँकि प्रकाशित सामग्री की सत्यता और वस्तुनिष्ठता के विषय में हर संभव प्रयास किया गया है, फिर भी इनकी प्रामाणिकता और शुद्धता के संबंध में एक्जिम्बैंक की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक, केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केन्द्र कॉम्प्लेक्स, कफ़ परेड, मुंबई - 400 005. फ़ोन : 2217 2600 फ़ैक्स : 2218 2572 ई-मेल : cag@eximbankindia.in
कृषि व्यापार समूह : agrigroup@eximbankindia.in/simaran.k@eximbankindia.in Website:www.eximbankindia.in

संपर्क नम्बर : अहमदाबाद: 26576852, बैंगलोर: 25585755, चंडीगढ़: 2641910/12, चेन्नै: 28522830, गुवाहाटी: 2237607, हैदराबाद: 23307816, कोलकाता: 22833419, नई दिल्ली: 23474800, पुणे: 26403000, अबिदजान : (225) 79707149, अदिस अबाबा: (251116) 630079, ढाका: +88 02 5504 2444, दुबई: (9714) 3637462, जोहानिसबर्ग: (2711) 3265103, लंदन: (4420) 77969040, सिंगापुर: (65) 653 26464, वाशिंगटन डी.सी.: (1202) 223-3238, यांगून : (95) 1389520